# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

**पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र विजय (आई0ए0एस0)**

**प्रकरण संख्या– 69/2017**

बउनवान

हरिशंकर पुत्र श्री किशन जाति–माली निवासी मण्डोला तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

**अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956**

उपस्थिति :–1. श्री सिमरनजीत सिंह, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

**निर्णय दिनांक– 31.03.2021**

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 06.10.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–मण्डोला, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 424 रकबा 0.12 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर जप्ती, बेदखली, 66/– रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है। अतिक्रमित आराजी की पैमाईश भी नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.10.2015 निरस्त किया जाना न्यायहित में होगा क्योकि अपीलांट ने तावान राशि भी जमा करवा दी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:52 IST
Reason: SelfAttested

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर, प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं दिया है, एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट ने बताये गये सम्पूर्ण अतिक्रमण से

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में भूमि खाली पडी हुयी है। इस संबंध में हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 11.04.17 पेश की गयी। साथ हीं कथन किया कि अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। उसके विरूद्व कोई तावान राशि बकाया नहीं है। अतः न्यायहित में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.10.2015 निरस्त फरमाया जावे।

4– इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 994/14 निर्णय दिनांक 27.11.2014 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5– हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु प्रकरण में हल्का पटवारी की रिपोर्ट पेश हुयी है तथा बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6– परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.2015 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1085/15 में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2015 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 06.10.2015 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 31[illegible] को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:52 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलेक्टर बारां (राज०)